

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक: 27 जुलाई, 2016

विषय— वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र, हल्द्वानी में 02 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी के निर्माण कार्य हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-106/नि.अ.क./350-कब्रि.चा.दिवारी/नैनीताल/2016-17, दिनांक 28.04.2016 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान में उक्त योजनान्तर्गत 'आयोजनागत' पक्ष में न्यून धनराशि का प्राविधान होने के फलस्वरूप जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी में संलग्न तालिका में उल्लिखित 02 कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी के निर्माण कार्य की अपरिहार्यता तथा धन की त्वरित आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित विवरणानुसार ₹ 208.77 लाख (₹ दो करोड़ आठ लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित करते हुए निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक उपयोग में लायी जाने वाली वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए अनुमोदित त्रिवर्षीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-01, दिनांक 01.01.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- कार्य पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए। धनराशि तभी आहरित की जायेगी जब सभी कार्यों के डी.पी.आर. नियमानुसार अनुमोदित हो गये हों।
- 3- स्वीकृत धनराशि का आगणन एवं व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त कार्य विशेष से सम्बन्धित कोई जांच बिन्दु लम्बित हो तो निदेशालय स्तर से धनराशि प्रदान करते समय समाधान अवश्य कर लिया जाये अन्यथा की स्थिति में पूर्ण दायित्व निदेशालय का होगा।
- 4- वित्तीय स्वीकृति के आधार पर निर्माण संगठन/कार्यदाई संस्था द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्माण संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विस्तृत आगणन के आधार पर तैयार की जायेगी।
- 5- उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो। किसी प्रकार का दोहराव पाये जाने पर संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- 6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाये।
- 7- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

- 8- परीक्षण के सन्दर्भ में नियोजन विभाग से समन्वय कर, परीक्षण सम्पन्न कराते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी एवं उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय कार्यदायी संस्था को देय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा। गुणवत्ता परीक्षण आख्या शासन को भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 09- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 10- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाए जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 11- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जायेगा।
- 12- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाय।
- 13- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 14- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप में प्राप्त कर ली जाय।
- 15- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 में निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 16- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 17- अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
- 18- राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित की जा रही धनराशि के प्रतिदान हेतु आवश्यक व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में करा दी जायेगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य आकस्मिकता निधि के लेखाशीर्षक "8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि लेखा-201-समेकित निधि के विनियोजन" तथा अन्ततः 'अनुदान संख्या-15' के अन्तर्गत 'आयोजनागत' पक्ष के लेखाशीर्षक "4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-11-कब्रिस्तानों में चाहर दिवारी का निर्माण" के मानक मद '24-वृहत निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

संलग्न- यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- 147 / XXVII-1 / रा.आ.निधि / 2016, दिनांक 26.07.2016

प्रतिलिपि: प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(श्रीधर बाबू अददांकी)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या-995/XVII-3/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्य, उत्तराखण्ड, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।

6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन नि., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, नैनीताल।
- ✓ 8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
W
(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।